IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

नक्सलवाद के विरूद्ध सरकार के सुरक्षात्मक प्रयासों का मूल्याँकन :–

मार्गदर्शक :–
डॉ. अविनाश कुमार लाल
राजनीति विज्ञान

शोधकर्ता :–
हर्षा साहू सहायक प्राध्यापक
पी.–एच.डी स्कॉलर

नक्सलवाद उग्र क्रातिकारी हिंसक विचारधारा है जो भारत की सुरक्षा, एकता, अखण्डता के लिये गंभीर खतरा है ही, साथ ही आदिवासी, पिछड़े इलाको ं के अशिक्षा सामाजिक अधिक पिछड़ापन तथा मुख्यधारा से उनकी दूरी का महत्वपूर्ा कारण है। नक्सलवाद की शुरूआत :– भारत मे ं नक्सली हिंसा की शुरूआत सन् 1967 मे ं पश्चिम बगं ाल के दार्जिलिंग जिला के नक्सलवादी क्षेत्र स ` समाज मे ं असमानता शोषण–गरीबो ं के विरूद्ध चारू मजूमदार तथा कानू सान्याल के नेतृत्व मे ं आरंभ हुआ जो कि पूर्ातः उग्रवाद माआवे ादी विचारधारा से प्रभावित था। 1967 से अब तक इनके विचारधाराओ ं के आधार पर तीन चरण –

1. प्रथम चरण – वर्ष 1967 स ` 1980 तक का समय मार्क्सवादी लेनिनवादी माआवे ादी विचारधारा से प्रेरित था।
2. द्वितीय चरण – वर्ष 1980 स ` 2004 तक का समय जमीनी अनुभव जरूरत और आवश्यकता के आधार पर
3. तृतीय चरण – वर्ष 2004 स ` वर्तमान तक का समय जिसने ये राष्ट्रीय स्वरूप मे ं उभरे तथा विदेशी संपर्क में आये।

छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलवाद की समस्या अपन ` शुरूआती दौर स ` ही मौजूद है गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश के 90 जिले नक्सलवाद से प्रभावित है जिसमे ं 14 जिले छत्तीसगढ़ राज्य के है। राज्य ने 2001 स ` 2019 तक की घटना में 1002 माआवे ादी मारे गये, 1232 सुरक्षा बल शहीद हुये तथा 1782 आम नागरिक हिसं ा का शिकार हुये तथा बड़ी सख्ं या मे ं 3896 माओवादियो ं ने आत्म समर्पण किया तथा मुख्यधारा से जुड़कर जीवनयापन का निर्णय लिया।

राज्य गठन के 20 वर्ष पूर्ण हो चुके है राज्य ने शिक्षा, संस्कृति, कृति, उद्योग, विद्युत, सुशासन हर क्षेत्र मे राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान रचे है किन्तु समय–समय पर होने वाली नक्सलवादी हिंसक गतिविधियो ने राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य की छवि को धूमिल किया है।

क्षेत्रफल दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग बस्तर वन संसाधन खनिज भण्डारो से समृद्ध व गौरवशाली तथा शांतिपूर्ण इतिहास का साक्षी रहा है किन्तु वर्तमान सूचना क्रांति से समय मे अपनी मूलभूत आवश्यकताओ सड़क, स्कूल, अस्पताल, रोजगार तथा शासन–प्रशासन की कल्याणकारी योजनाओ से अनभिज्ञ तथा लाभ से वंचित है जिसका मुख्य कारण अपने आंदोलन के प्रारंभिक दौर से ही यहाँ नक्सलवाद की मौजूदगी तथा पिछड़ापन है। नक्सलवाद समस्या के स्थायित्व के मूल कारण :–

1. अशिक्षा – शैक्षणिक संस्थाओं की खराब स्थिति
2. सामाजिक पिछड़ापन
3. आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं – बेरोजगारी के शिकार
4. अलगाववाद की भावना
5. जागरूकता की कमी
6. प्रशासन तथा आम जन मे संपर्क जुड़ाव की कमी।
7. सुरक्षा – साधनों की कमी आदि है।

महत्वपर्णू नक्लसवादी घटनाएँ :–

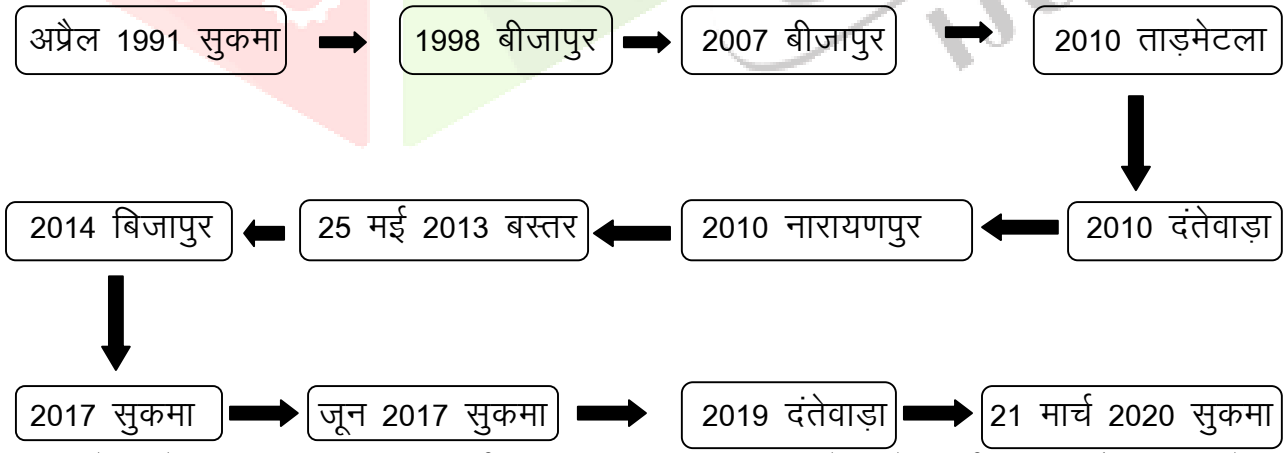

अप्रैल 1991 सुकमा → 1998 बीजापुर → 2007 बीजापुर → 2010 ताड़मेटला → 2010 दंतेवाड़ा → 2010 नारायणपुर → 25 मई 2013 बस्तर → 2014 बिजापुर → 2017 सुकमा → जून 2017 सुकमा → 2019 दंतेवाड़ा → 21 मार्च 2020 सुकमा

उपरोक्त रेखांकित चित्र द्वारा सिर्फ कुछ नक्सलवादी घटनाओ को दर्शाया गया है वास्तव मे घटनाओ की कुल संख्या इससे कहीं ज्यादा है इसमें से सबसे बड़े हमले जिन्होनें राज्य प्रशासन के सुरक्षा तंत्र को हिला दिया तथा सरकार को त्वरित कार्यवाही हेतु अग्रसर किया वे हैं –

1. 25 मई 2013 – बस्तर जिलेके दरभा घाटी मे ं हुये नक्सली हमले मे ं महेन्द्र कर्मा, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष स्व. श्री नंदकुमार पटेल तथा विद्याचरण शुक्त सहित 30 से अधिक लोगों की बर्बरता से हत्या की गयी।
2. 1 मार्च 2020 – सुकमा जिले में जवानों पर हमला कर 25 जवान शहीद। 3. अप्रैल 2021 – सुकमा जिला में जवानों पर हमला कर 22 जवान शहीद। नक्सलियों द्वारा किये गये निदंनीय बर्बरता पूर्वक कृत्यों के प्रत्युत्तर में राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रसास किये जा रहे विकास कार्यक्रम तथा पुलिस, रक्षा बल की साझा रणनीति बनाकर प्रयास जारी है जिसके सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुये – पिछल ं 7 सालो ं मे ं नक्सली हिंसा मे ं लगभग 62% कमी आयी है। ये सब मुमकिन हो पाया है। राज्य शासन, पुलिस विभाग, आम नागरिक तथा गैर राजनीतिक संगठन द्वारा अभियान–कार्यक्रम चलाये गये, वर्तमान मे ं भी जारी है चंूकि नक्सवाद एक विचारधारा के रूप ने न सिर्फ हिंसक कार्यो का अंजाम देती है साथ ही यह गरीब–बेरोजगार ग्रामीण युवका ं का ं मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रभावित कर अपने दलों मे ं शामिल भी करती है जिस बात पर ध्यान देते हुए हमारे प्रशासन तथा पुलिस विभाग द्वारा नक्सलियो ं के विरूद्ध जमीनी लड़ाई तो जारी रखी ही गयी है साथ ही भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी पहल शुरू की गइ ं है जिनमे ं से सरकार के कुछ प्रयासों अभियान का उल्लेख नीचे किया जा रहा है –

1. ग्रीन हंट अभियान
2. प्रहार
3. सलवा जूडूम
4. लोनवर्राटू

❖ <u>ग्रीन हंट अभियान (शुरूआत 2009)</u> :– सन् 2009 स ं यह अभियान लाल गलियारे क्षेत्र वाले 5 राज्यो ं ने चलाया गया जो राज्य है – छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, तेलगांना आपरेशन ग्रीन हंट नक्सयिो ं के विरूद्ध भारत सरकार की पैरामिलिटरी बल तथा राज्य बल द्वारा उन्हें आक्रामक तरीके स ं बाहर खदेड़ने के लिये चलाया गया था जिसमे ं मानव रहित हवाई वाहन तथा सैटेलाईट फोन का प्रयोग किया गया। ग्रीन हंट अभियान चर्चा मे ं 2014 में आया जब नक्सलियों द्वारा सुकमा में घात लगाकर सैन्य बलो पर हमला किया जो ग्रीन हंट अभियान के विरोध में था।

8 जनवरी 2016 को इस अभियान को केन्द्रीय सरकार की पैरामिलिटरी फोर्स ने पुनः आरंभ किया जिससे यह चर्चा में रहा।

''ग्रीन हंट शब्द का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ पुलिस अधिकारियो ं द्वारा किया गया जिसके पश्चात् मीडिया द्वरा ग्रीन हंट शब्द का उपयोग व्यापक पैमाने पर किया गया। केन्द्र सरकार अपने नक्सल विरोधी

आक्रमण के लिये ग्रीन हंट शब्द का इस्तेमान नहीं करती । वर्तमान मे ं यह अभियान बदं नही किया गया है।

क्रं.	अभियान	वर्ष
1.	सलवा जूडूम	2005
2.	ग्रीन हंट	2009
3.	प्रहार प्रथम	2017
4.	प्रहार द्वितीय	नवम्बर 2017
5.	लोन वर्राटू	2020

❖ ऑपरेशन प्रहार प्रथम :– नक्सलियो ं के विरूद्ध ऑपरेशन प्रहार अभियान 22 जून 2017 को आरम्भ किया गया था जा ` 56 घंट ` चला था पुलिस विभाग द्वारा बताया गया था कि यह नक्सलियों के विरूद्ध अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इस पूरे अभियान को STF, DRG, FRPF की काबे रा बटालियन के साथ सयं ुक्त रूप स ` किया गया जिस ` लगभग 15–25 नक्सलियों के मारे जाने का पुष्टि हुई थी।

❖ ऑपरेशन प्रहार द्वितीय :– नवम्बर 2017 को टास्क फोर्स के साथ पुनः आरम्भ किया गया जिसमे ं STF, DRG, FRPF, ANTF की टीम ने साथ काम किया था जिसमे ं लगभग 63 नक्सलियों के मरने की पुष्टि हुई थी यह ऑपरेशन नारायणपुर जिले में शुरू किया गया था। वर्तमान में खबरे है कि सरकार ऑपरेशन तृतीय शुरू करने की तैयारी मे ं है किन्तु अभी

तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

❖ सलवा जूडूम :– सलवा जूडूम अर्थात शांति यात्रा, सन् 2005 मे ं महेन्द्र कर्मा द्वारा यह अभियान शुरू किया गया था जिसके तहत ग्रामीण आदिवासियो ं को हथियार देकर उन्हें स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाया गया था किन्तु मानवाधिकार सस ं था / कार्यक्रम ने इस अभियान को खूनी संघर्ष युक्त अभियान बताया तथा इसके औचित्य पर प्रश्न खड़े किये। काफी विरोध पश्चात् सन् 2011 मे ं मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तथा न्यायालय द्वारा इसे

अवैध घोषित कर दिया गया।

❖ लोन वर्राटू :– गोडं ी भाषा का शब्द है लोन वर्राटू जिसका अर्थ है घर वापसी, सरकार द्वारा नक्सलियोंके विरूद्ध जमीनी स्तर पर लड़ाई जारी है किन्तु इस बार इसक ` साथ ही सरकार द्वारा मनोवैज्ञानिक भावानात्मक प्रयास किये गये है। दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा 2020 मे ं लोन वर्राटू अभियान की शुरूआत की यह दंतेवाड़ा के

कटके ल्याण क्षेत्र से शुरू की गयी है। जिसके तहत गोडं ी भाषा मे ं पोस्टर अभियान द्वारा नक्सलियों स ` मार्मिक अपील की जा

रही है कि वह मुख्यधारा मे ं लौटे तथा सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ लते हुये रोजगार कर े या गांवों में रहकर कृषि करें।

अभियान का सकारात्मक परिणाम आने लगा है पिछल े 9 महीने मे ं ही लगभग 400 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष आत्म समर्पण किया है। मूल्याँकन :–

- जनता का पक्ष :– नक्सलियो ं की हिंसक गतिविधी तथा प्रशासन के मध्य नागरिकों की स्थिति दयनीय है दोनो पक्षो के प्रत्युत्तर गतिविधियो ं मे ं नागरिको ं की बीच मे ं फंसकर, हिंसा के शिकार हो रहे है। नक्सलियों द्वारा मुखबरी के शिकार में हत्या कर दी जाती है और कभी कभी शक के आधार पर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है जिसमे ं न्याय प्राप्ति
  मे ं भी काफी लेट लतीफी देखा गया है सरकारी रिकार्ड के आधार पर 20 वर्षो में 2000 नागरिको ं की हत्या कर दी गयी है।
- सरकार का पक्ष :– सरकार तथा पुलिस प्रशासन का कहना है उपरोक्त अभियानों व सुरक्षा व्यवस्था ने सुधार के पश्चात पिछले कुछ वर्षो मे ं नक्सल गतिविधियो ं मे ं कमी आयी है पिछल े 7 वर्षो मे ं कमी देखी गयी है निरन्तर प्रयास जारी रख नक्सलवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे।
- स्थिति मे ं सुधार हेतु सुझाव :– सबसे पहले सरकार/प्रशासन तथा जनता के मध्य मजबतू सपं र्क तंत्र स्थापित करना आवश्यक है आम नागरिको ं की सपं र्क बोली से प्रशासनिक अधिकारियोंको दक्ष किया जाये जिससे उनके मध्य दूरी समाप्त हो तथा व जागरूकता पवू र्क प्रशासन का सहयोग कर सके इस संघर्ष से निपटने मे। निष्कर्ष :–

छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियो ं के आत्मसमर्पण के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है। नक्सली इस अभियान के खिलाफ हैं, लेकिन कई बड़े नक्सली कमांडरों ने सरेंडर भी किया है। इसमें अपनी कोई भूमिका नहीं मानते व कहते हैं कि सरकारो ं की अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धताए ं होती है और इसमे ं उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। परन्तु केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की साझा रणनीति नक्सलियों के खात्मे के लिए उनक े ताबूत मे ं आखिरी कील ठोकने का काम करगे । या उन्हे आत्मसमर्पण की दिशा की आरे उन्मुख कर समाज की मुख्य धारा तक लायेगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि यदि दोनो ं सरकारो ं की साझा रणनीति काम कर जाती है तो राज्य से नक्लसवाद का सफाया होना तय है। जागरूकता पवू र्क, सहयोग तथा सुरक्षा तंत्र को दुरस्त कर नक्सलवाद स े लड़ाई जीती जा सकती है, पिछड़ापन एक महत्वपू र्ा कारक नजर आता है जिससे

नक्सलवाद को अनूकुल स्थिति प्राप्त होती है अतः सरकार को क्षेत्रों तथा नागरिको ं के विकास का हर सभ्ं ाव तथा त्वरित प्रयास करना होगा।

सदं र्भ सूची :– अ. – पुस्तकें – नक्सलवाद – डॉ. एस.

के मिश्रा

ब. – समाचार पत्र –

1- Indian Express – 09 Jan. 2016
2- Times of India – 19 June 2016
3- पत्रिका – 02 जन. 2018
4- News 18 हिंदी

स. – न्यजू चैनल

1- IBC 24 – 02 July 2020